(d) if so, what action has been taken by Government to put an end to the attacks on Tamil fishermen by the Sri Lankan army?

THE PRIME MINISTER (SHRI I.K. GUJRAL): (a) to (d) Three incidents of firing at Indian vessels, involving five boats, resulting in the death of one fisherman and injuries to six others, were reported to Government in the month of June 1997. The Sri Lankan Government has denied the involvement of their Navy in two of the three incidents reported in June 1997, while their formal response is awaited with regard to the third incident.

Of the three reported incidents, tne Sri Lankan authorities have denied involvement of their armed forces in an incident of firing at a fishing boat between Dhanushkodi and Kachchativ and another reported incident involving three

Indian vessels between Thalaimannar and the Delft Island. The other incident, on which a Sri Lankan response is awaited, also relates to areas well within Sri Lankan waters close to Kankesanthurai and, therefore, does not have a bearing on the 1974 agreement.

Government have protested at every incident of violence against Indian fishermen and have emphasised to the Government of Sri Lanka the need for restraint in dealing with the fishermen. PM, during his visit to Sri Lanka as the then EAM in January 1997, conveyed our serious concern at the incidents of violence against Indian fishermen. Both sides agreed on the need to take steps to avoid untoward incidents in each others' waters and to address the problems faced by the fishermen in a spirit of compassion and understanding. Further discussions on problems faced by the fishermen were held during a visit by a Sri Lankan delegation in February, 1997. Both sides agreed to examine modalities of ensuring the safety of fishermen straying across the Interna-$_t$ tional Boundary Line.

Ninth Fivc-Ycar Plan outlay for States

*33. SHRI BRATIN SENGUPTA:
SHRI MOHINDAR SINGH KALYAN:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(o) what is the outlay sanctioned by the Planning Commission for the Ninth Five Year Plan in respect of different States of the country; and

(b) what targets have been set in the Plan for agricultural and industrial production and what would be the rate of growth expected to be achieved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DE-HARESHWAR SAVANOOR): (a) and (b) The outlays mutually agreed to at the level of Deputy Chairman and Chief Ministers for the Ninth Five Year Plan in respect of different States are given in the statement (See below). The Ninth Plan outlays in respect of Bihar, Punjab, Tamil Nadu and the seven North Eastern States have not yet been finalised. In the Approach Paper to the Ninth Five Year Plan, Agriculture sector has been identified as a priority area and it is envisaged to achieve an agricultural growth rate of 4.5% per annum. As regards Industrial Sector, the projected growth rate of value added during Ninth Plan for the country is 9.3%. Statcwise targets of growth rate in the Agricultural and Industrial sectors have not been set.

Statement

Agreed Outlays for Ninth Five Year Plan (1997—2002)-States

(Rs. Crore)

SI. No.	States	Agreed Outlay
1.	Andhra Pradesh	25150.00
2.	Arunachal Pradesh	*
3.	Assam	*
4.	Bihar	*

Sl. No,	States	Agreed Outlay
5.	Goa	1500.00
6.	Gujarat	28000.00
7.	Haryana	9310.00
8.	Himachal Pradesh .	5700.00
9.	Jammu & Kashmir	@@
10.	Karnataka	23400.00
11.	Kerala	16100.00
12.	Madhya Pradesh	20075.00
13.	Maharashtra	36700.00
14.	Manipur	*
15.	Meghalaya	*
16.	Mizoram	*
17.	Nagaland	*
18.	Orissa	15000.00
19.	Punjab	*
20.	Rajasthan	22000.00
21.	Sikkim	1600.00
22.	Tamil Nadu	*
23.	Tripura Uttar	*
24.	Pradesh West	46340.00
25.	Bengal	16900.00

पाकिस्तान के सब आतंकवादी और विध्वंसक कार्यवाहियों को रोकने के संबंध में सहमति

*34. **श्री एस.-0 एस0 अहलुवालिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता के पश्चात् कुछ मुद्दों पर सहमति हो गई है तथा कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या उक्त वार्ता में पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवादी और विध्वंसक कार्यवाहियों को बढ़ावा देने को रोकनें के संबंध में कोई सहमति अथवा विचारों का कोई आदान-प्रदान हुआ हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ) विदेश सचिव स्तर पर फिर से

शुरू हुई बातचीत का दूसरा दौर इस्लामाबाद में 19-23 जून, 1997 को हुआ था। बातचीत के निष्कर्ष पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ था। दोनों पक्षों ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मसलों को हल करने का निर्णय लिया था:

(क)विधासोत्पादक उपायों सहति शान्ति और सुरक्षा,

(ख) जम्मू और कश्मीर, (ग) सियाचीन, (घ) तुलबुल नौवहन परियोजना, (ड) सरक्रीक, (च) आतंकवाद और औषधियों का अवैध व्यापार, (छ) आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग, (ज) विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण संबंधों का संवर्द्धन। इन सभी मसलों का समेकित तरीके से हल निकालने के लिए उपयुक्त स्तरों पर कार्यकारी दलों सहित एक तंत्र का गठन करने के लिए भी सहमत हुए। उपरालिखित (क) और (ख) से सम्बद्ध मसलों पर विदेश सचिव स्तर पर कार्यवाही की जाएगी जो सभी कार्य दलों के कार्यों को समन्वित और कार्य में हुई प्रगति पर भी नजर रखेंगे दोनों पक्ष एक –दूसरे के विरूद्ध विरोधी दुष्टाचार और भड़कने वाली गतिविधियों से बचने के लिए हर संभव उपाय करने पर भी सहमत हुए।

संयुक्त वक्तव्य में भारत और पाकिस्तान के बीच व्यवापक,रचनात्मक और स्थायी बातचीत के आधारों का प्रावधान हैं। यह ऐसी रूपरेखा है जिसके अन्तर्गत विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातचीत होगी। हम इसे विश्वास, मित्रतापूर्ण और सहयोग के संबंध बनाने के उद्देश्य से पाकिस्तान को एक विशाल मंच पर जाने के अपने प्रयासों की दिशा में बढ़े कदम के रूप में मानते हैं।

यद्यपि बातचीत मुख्यत: भावी चर्चाओं के लिए रूप-रेखाओं और तंत्र-रचना पर केन्द्रित रही किन्तु जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान के सक्रिय प्रोत्साहन के बारे में अपनी चिन्ताएं स्पष्ट रूप से बताई गई थीं और पाकिस्तान को जम्मू और कश्मीर के बारे में तथ्यात्मक स्थिति से फिर से अवगत कराया गया।

सूचना पाने के अधिकार को लागू किया जाना

*35. **श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्य सरकारों ने सूचना पाने के लिए अधिकार को प्रयोग के तौर पर लागू किया हैं;

(ख) मध्य प्रदेश में उन विभागों और जिलों का ब्यौरा क्या हैं जहां इसे लागू किया गया हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने भी इसे प्रयोग के तौर पर किसी विभाग में लागू किया हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन विभागों के नाम क्या हैं?

* :Plon size not yet decided.
@@ :To be finalised between Rs. 9000 and Rs. 10000 crore.